

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 964

17 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

कच्चे इस्पात का उत्पादन

964. श्री एम. चन्द्राकाशी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित और उपभोग की गई कच्चे इस्पात की मात्रा का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या भविष्य में इस्पात की मांग हेतु रुझान का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;
- (घ) गत दो वर्षों के दौरान घरेलू इस्पात उद्योग के वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है और घरेलू इस्पात उद्योग की खराब स्थिति के क्या कारण हैं; और
- (ङ) देश में इस्पात कंपनियों/उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क): गत तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17, 2017-18 और चालू वर्ष के दौरान भारत द्वारा कूड इस्पात का उत्पादन और फिनिशड इस्पात की खपत के आँकड़े नीचे दर्शाए गए हैं

वर्ष	कूड इस्पात उत्पादन (एमटी)	फिनिशड इस्पात खपत (एमटी)
2015-16	89.79	81.52
2016-17	97.94	84.04
2017-18	103.13	90.71
अप्रैल-अक्टूबर 2018*	61.03	55.99

स्रोत: जेपीसी;*अनंतिम

(ख) और (ग): जी हाँ। अध्ययन में शामिल किए गए व्यापक क्षेत्रों में अवसंरचना और निर्माण, रक्षा, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता तथा पूँजीगत सामग्रियाँ शामिल हैं।

(घ): गत दो वर्षों के दौरान घरेलू इस्पात उद्योग का वित्तीय निष्पादन निम्नवत् है:-

मुख्य इस्पात कंपनियों का कार्य-निष्पादन

(आँकड़े करोड़ रुपये में)

कंपनी का नाम	कर-पश्चात लाभ	
	2016-17	2017-18
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल)	-2833	-481.71
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	-1263	-858
टाटा स्टील	3444.55	4169.55
जेएसडब्ल्यू	3576.54	4625
जेएसपीएल	-986.45	-361.61

स्रोत: कंपनी वेबसाइट

आयातों से घरेलू इस्पात की कीमतों और घरेलू इस्पात उत्पादकों की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कीमतों के गिरने से घरेलू इस्पात उत्पादकों की बिक्री में कमी हुई। इस अवधि के दौरान भारतीय इस्पात कंपनियों ने उनके लाभों में भारी कमी का सामना किया। कम प्राप्तियों और उससे होने वाली हानि के परिणामस्वरूप इस्पात कंपनियों की ऋण लेने की क्षमता प्रभावित हुई जिससे इस क्षेत्र में डूबत ऋण की समस्या बढ़ गई।

(ङ): सरकार ने देश में इस्पात कंपनियों/उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- न्यूनतम आयात शुल्क (एमआईपी), एंटी-डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी जैसे विविध व्यापार उपचारात्मक उपायों को अधिसूचित किया गया है;
- आरबीआई और वित्त मंत्रालय के माध्यम से वित्तीय पुनर्संरचना मानकों को सरल करना, अर्थात् 5:25 योजना और दबावग्रस्त आस्तियों की दीर्घकालिक संरचना के लिए योजना (एस4ए);
- इनपुट लागत को कम करने, आयात प्रतिस्थापन और घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाएं आरंभ की;
- सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने के लिए नीति;
- स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) की स्थापना; सार्वजनिक/पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में डिजाइन और विनिर्देशन तैयार करते समय जीवन चक्र लागत विश्लेषण का समावेश करने के लिए जीएफआर दिशा-निर्देश संशोधित किया जिससे इस्पात की माँग सृजित होगी और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्पात कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
